response, 22 bidders, Indian as well as Foreign, submitted their proposals.

(c) and (d) Bidders have not been shortlisted so far.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

Garment Exports from India

*114. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the total exports of garments from India during the last three years, and the major countries importing garments;

(b) the break-up of garments export in cotton, silk and handloom during the last three years; and

(c) the target fixed for export of garments for the year 1996-97?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) The exports of garments (cotton, synthetic and woollen) from India during the last three years were as follows:

	Value in U.S. Million Dollars
1993-94	3713.65
1994-95	4433.83
1995-96	4453.31

The major importing countries of garments from India are the E.U. Member States, the U.S.A., Canada, the U.A.E., Japan, Switzerland and Australia.

(bj The exports of cotton garments (knitted, handloom, rnillmade) silk garments (Mulberry & Mixed/Blended) and handloom garments (cotton, synthetic and woollen) during the last three years were as follows:

Value in U.S. Million Dollars

	1993-94	1994-95	1995-96
(i) Cotton garments (knitted, handloom and millmade)	2744.40	3127.70	3121.40
(ii) Silk garments (Mulberry & Mixed/Blended)	82.08	86.04	62.04
(in) Handloom garments (Cotton, Synthetic & Woollen)	25.80	42.00	28.20

(c) A target of US $ 4750 million has been fixed for the export of garments during 1996-97.

विद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर को अनिवार्य किया जाना

*115. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्लः**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोलाः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर को अनिवार्य रूप से लागू करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या रक्षा मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच समन्वय रखने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) और (ख) जी नहीं, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण को विद्यालयों और महाविद्यालयों में अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) बड़ी मात्रा में वित्तीय तथा आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए और लोकतांत्रिक भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण स्वैच्छिक आधार पर रखा गया है।

(घ) जब भी किसी विषय पर विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता होती है तो मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श किया जाता है।